भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †1538

दिनांक 12.12.2023 को उत्तरार्थ

पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था

†1538. श्री एस. मुनिस्वामी:

क्या ***पंचायती राज*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय सभी राज्यों में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाने की योजना बना रहा है;

(ख) किन राज्यों में जिला परिषदों और तालुका पंचायतों के चुनाव लंबित हैं और वहां अदालती मामलों के कारण केवल प्रशासक हैं;

(ग) कर्नाटक राज्य में जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनावों की स्थिति क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कर्नाटक राज्य में जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों के चुनावों में अधिक देरी हो रही है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ख में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन, संविधान के भाग-9 के प्रावधानों के अनुसार, किया जाएगा। लेकिन, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक नहीं है। वर्तमान में, संविधान के अनुच्छेद 243ड में

उल्लिखित कुछ क्षेत्रों क्षेत्रों को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली मौजूद है।

(ख) से (ङ) जिन राज्यों में मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के चुनाव लंबित हैं, वे हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मणिपुर। हालाँकि, इन राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में ये चुनाव अदालती मामलों के कारण लंबित हैं। संविधान के अनुच्छेद 243ङ के अनुसार, समय पर चुनाव कराना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मंत्रालय ने अप्रैल, 2022 में कर्नाटक राज्य को उन प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने की सलाह दी है जो ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव कराने से रोक रहीं हैं। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान उन पंचायतों को जारी नहीं किया जाता है जहां चुनाव नहीं हुए हैं।

*****